संपादकीय

अमेरिका के टैरिफ का कहर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मनमाने टैरिफ हमले और चीन की जवाबी कार्रवाई से विश्व के तमाम शेयर बाजार लहूलुहान हुए हैं। कई अन्य देशों की भी जवाबी कार्रवाई के फैसले से दीर्घकालीन व्यापार युद्ध की आशंका बलवती हो गई है। जिससे पूरी दुनिया में मंदी आने की चेतावनी दी जा रही है। निश्चित तौर पर इससे आर्थिक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इस संशय और अनिश्चितता के चलते शेयर बाजार में बड़े पैमाने पर बिकवाली से दुनिया के तमाम शेयर बाजार धराशायी हुए हैं। निवेशकों को लाखों करोड़ का नुकसान हो रहा है। आने वाले समय में टैरिफ वॉर के और बढ़ने की आशंका है क्योंकि चीन ने नौ अप्रैल को होने वाली विश्व व्यापार संगठन की बैठक में 'नई व्यापार चिंता' के रूप में अमेरिका की टैरिफ नीति का मुखर विरोध करने का फैसला किया है। चीन का मानना है कि अमेरिका के एकतरफा संरक्षणवाद का दुनिया के देशों को विरोध करना चाहिए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली की सुरक्षा के लिये एक व्यापक गठबंधन बनाने की जरूरत बतायी है। इन हालात में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ थोपने के फैसले को वापस लेंगे या फिर पहले की तरह टैरिफ लगाने की धौंस देते रहेंगे। वैसे इस बात की संभावना कम ही है कि जिद्दी ट्रंप अपने बढ़े कदमों को पीछे खींचेंगे। यहां सवाल यह भी है कि ट्रंप के टैरिफ का जवाब देने वाले देश पलटवार करने में कितने सक्षम हैं। वहीं भारत ने दीर्घकालीन व व्यापक हितों को देखते हुए टकराव टालने का प्रयास किया है और बातचीत का रास्ता चुना है। लेकिन इस अनिशिचतता के दौर में निवेशकों में बढ़ती असुरक्षा ने भारत सरकार पर नीतिगत फैसले लेने के लिये दबाव बनाया है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी संभावना है कि चीन व प्रतिकार करने वाले अन्य देशों के दबाव के कारण ट्रंप अपनी आक्रामक रणनीति को लंबे समय तक जारी नहीं रख पाएंगे।

विडंबना यह है कि अमेरिका राष्ट्रपति के इन कदमों से खुद अमेरिका के लिये भी बड़ी आर्थिक चुनौती पैदा हो सकती है। येल विश्वविद्यालय में बजट लैब के एक विश्लेषण के अनुसार ट्रंप सरकार के प्रतिशोधात्मक टैरिफ से औसत अमेरिकी परिवार को सालाना चार हजार दो सौ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं अमेरिका में मंदी और तेज मुद्रास्फीति का खतरा भी मंडरा रहा है। वहीं भारत जैसे अन्य विकासशील व विकसित देशों को आशा है कि वैश्विक व घरेलू दबाव ट्रंप को उनकी भूल का अहसास कराएगा। जिससे वे अधिक आर्थिक अराजकता पैदा करने वाले फैसलों से पीछे हटेंगे। वैसे एक हकीकत यह भी है कि अमेरिका अपने कई उत्पादों के लिये अन्य देशों पर निर्भर है। उसके उद्यमियों ने भी दूसरे देशों में औद्योगिक यूनिट लगा रखे हैं। ऐसे में उन देशों पर टैरिफ लगाने से अमेरिकी जनता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के दाम भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेंगे। यही वजह है कि अमेरिका के शेयर बाजारों में भी बड़ी गिरावट देखी गई है। जिसका असर पूरी दुनिया पर भी दिख रहा है और स्थितियां कोरोना काल के संकट जैसी बन गई हैं। वैसे आज भी दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं कोरोना काल से पूर्व की आर्थिक स्थिति पर लौटने के लिये संघर्षरत हैं। कमोबेश ये स्थितियां बड़े आर्थिक संकट की आहट दे रही हैं। जिसकी वजह है कि अमेरिका समेत अन्य देशों में निवेश बाधित होने, उत्पादन में गिरावट, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से वैश्विक स्तर पर महंगाई उत्पन्न होने की चिंताएं बढ़ रही हैं। जिसका तमाम क्षेत्रों पर असर पड़ने से आम लोगों का जीवनयापन कठिन होता जाएगा। खपत कम होने से अर्थव्यवस्था का चक्र धीमा हो जाएगा। यही वजह है कि ट्रंप के मनमाने टैरिफ युद्ध से दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं खुद को बचाने की जद्दोजहद में जुटी हैं। हालांकि, खुद अमेरिका भी इसके दुष्परिणामों से अछूता नहीं रहेगा। निवेशकों की घबराहट से उसकी अर्थव्यवस्था भी चरमराएगी। आने वाले वक्त में उसके दांव ही उलटे पड़ने वाले हैं। घोर संरक्षणवाद के चलते वह कालांतर में शेष दुनिया से कट जाएगा।

'ट्रम्प का टैरिफ' ईर्ष्या से आया ख्याल, अब दुनिया है बेहाल..!

ऋतुपर्ण दवे

ट्रम्प के मन में टैरिफ को लेकर आया विचार एकाएक नहीं है। उनके व्यवसाय को जापानियों से मिली चुनौतियों के चलते 1990 के दशक में की घटना है जिससे क्रुद्ध ट्रम्प आज पलटवार कर रहे हैं। यह अर्से से उनके मन में पाला हुआ मंसूबा है। वास्तव में ट्रम्प के मन में जापानियों की प्रतिभा को लेकर पनपा ईर्ष्या भाव ही आज उनके टैरिफ की असल वजह है। वो मानते हैं कि जब मुक्त व्यापार अस्तित्व में नहीं था तब जापान, अमेरिका के बाजार में जबरदस्त पैठ बना रहा था, लेकिन अपने यहां व्यापार करना असंभव सा कर दिया था।

बस यही टीस बिजनेसमैन ट्रम्प को घर कर गई और उनके मन में एक गांठ बन गई। हालांकि उसी दौर में उन्हें नगदी की जबरदस्त जरूरत हुई और मजबूरन जापान की ओर आस भरी निगाहों से देखने लगे। लेकिन ट्रम्प 1980 के दशक से ही इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि मशहूर जापानी निवेशक रॉकफेलर अमेरिकी ब्रांड्स और संपत्तियों के अधिग्रहण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे उनका नजरिया ऐसा बदला जो आज आयात पर टैरिफ के सच के रूप में सामने है। यहीं से उनके दिमाग में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का मंसूबा भी बना और वो लंबी रणनीतियों और विचारों को लोगों से सार्वजनिक मंच पर जाहिर भी करने लगे।

1987 में ट्रम्प की किताब ट्रंप- द आर्ट ऑफ द डील में अमेरिकी व्यवसाय पर उनकी विस्तृत सोच के साथ मंशा भी झलकती है। लोकप्रिय द ओपरा शो के होस्ट ओपरा विनफ्रे के साथ भी तभी एक लाइव कार्यक्रम में साफ-साफ कहना कि अमेरिकी विदेश व्यापार नीति को वो कैसे सबसे अलग तरीके से संभालेंगे और इससे अमेरिका के लिए सही कीमत वसूलेंगे उनका रणनीतिक शो था। इतना ही नहीं ट्रम्प ने अपने विचारों को एक खुली चिट्ठी के रूप में अमेरिका के सर्वाधिक लोकप्रिय तीन समाचार पत्रों में भी बतौर विज्ञापन प्रकाशित करवाया जिसमें उनके एक लाख डॉलर खर्च हुए थे। मतलब उनका नजरिया पहले ही साफ हो चुका था। लेकिन यह भूलना चाहिए कि उनकी सोच और वास्तविकता में तब और अब में काफी फर्क है। आज अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वन्दी चीन है न कि जापान। 1990 के दशक के युवा रियल एस्टेट डेवलपर ट्रम्प की सोच आज भी वही है जबकि समय के साथ काफी कुछ बदल गया है। लेकिन ट्रम्प हैं कि मानते नहीं। बतौर राष्ट्रपति और व्यवसायी ऐसी सोच अंतर्राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हो सकती है। जैसा कि झलक रहा ह ै इससे अमेरिका में विदेशी व्यापारिक निवेश घटेगा जिसका अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन पर भी असर पड़ेगा।

सौ देशों की अमेरिकी डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ वाली सूची में भारत भी शामिल है जिस पर 26 प्रतिशत टैरिफ है जो कई एशियाई देशों की तुलना में कम है। भले ही भारत पर इसका प्रभाव अभी कम पड़े। लेकिन भविष्य को लेकर कोई गारंटी भी तो नहीं कि कब और कितना बढ़ जाए? इधर चीन ने भी अमेरिका पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है। जिस पर तिलमिलाए ट्रम्प ने 9 अप्रेल तक इसे वापस नहीं लेने पर 50 प्रतिशदत टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। अगर अमेरिका अपने हिसाब से चलने की जिद करेगा तो चीन भी आखिर तक लड़ेगा।

इधर ब्लूमबर्ग की हालिया सूची बताती है कि ट्रंप के करीबी मस्क की कुल नेटवर्थ 300 अरब डॉलर के नीचे चली गई है। जनवरी 2025 से अब तक 135 अरब डॉलर यानी करीब 12 लाख करोड़ रुपये का नुकसान उठा चुके हैं। इसी सोमवार को अमेरिकी बाजार में आई गिरावट से मस्क को करीब 40 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ जबकि बीते हफ्ते दो दिन में ही मस्क के 31 अरब डॉलर डूब गए। इस तरफ ट्रम्प के अघोषित टैरिफ वार से विश्व में सबसे नुकसान उठाने वालों की सूची में मस्क 6वें क्रम पर आ चुके हैं। कुल मिलाकार आसार अच्छे नहीं है।

नए बजट में ग्रामीण विकास के लिए 1,88,754 करोड़ तथा किसान कल्याण के लिए बीते बरस की तुलना में 11 प्रतिशत ज्यादा यानी 1.71 लाख करोड़ रुपयों का बजट में प्रावधान बताता है कि हमारी अपने आर्थिक मोर्चों पर कैसी तैयारी है।

भले ही 02 अप्रैल 2025 को ट्रम्प ने अमेरिका का मुक्ति दिवस बता रहे हों। लेकिन जिस तरह से दुनिया भर के शेयर बाजार धराशायी हुए, उससे कुछ अलग ही समझ आ रहा है। ट्रम्प भले ही कहें कि हमारे करदाताओं को 50 से अधिक वर्षों से लूटा जा रहा है। लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला आदेश उनकी ईर्ष्या, खीझ और अजीब दूरगामी सोच ही दर्शाता है।

अब अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर यूरोपीय यूनियने के टैरिफ के लिए 9 अप्रैल का इंतजार करना होगा, जिस पर मतदान होना है। यदि यह भी जस का तस जैसे रहा तो आसार और बिगड़ सकते हैं। पहले ही दुनिया भर के शेयर बाजार धड़ाम हो चुके हैं। खुद अमेरिका भी इसी से अछूता नहीं है।

ट्रम्प का अमेरिका में ही विरोध होने लगा है। उन्हे न केवल तानाशाह बल्कि अर्थव्यवस्था को तहस-नहस करने वाला सनकी तक कहा जाने लगा है। सभी 50 राज्यों में 150 संगठनों 1200 से ज्यादा प्रदर्शनों में हजारों का जुटना बताता है कि चिंता कितनी गंभीर है। हैंड्स ऑफ नाम के इस प्रदर्शन में शनिवार को हजारों लोग जुटे। 2017 में महिला मार्च और 2020 में ब्लैक लाइव्स आन्दोलन के बाद ट्रंप का ऐसा भारी विरोध हो रहा है। असल में एलन मस्क का दखल भी अमरीकियों को पसंद नहीं आ रहा है। उन पर नौकरी में छंटनियों के मंसूबों सहित सत्ता हथियाने जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। इधर भारत और खुद अमरीका सहित दुनिया भर के शेयर बाजारों में आज खुलते ही जबरदस्त तो कहीं ऐतिहासिक गिरावट देखी जा रही है। निश्चित रूप से शुभ संकेत नहीं है

व्यावसायिक हितों और तमाम दूसरे मामलों में सतर्क दुनिया ने एकजुट होकर ट्रम्प को जवाब देना शुरू कर दिया है जिससे वैश्विक ट्रेड वार की आशंका बढ़ गई है। काश ऐसा नहीं होता और ट्रम्प समझदारी और विवेक से काम लेते। दुनिया में कम से कम खुशहाल इंसानियत के लिए तो सौदेबाजी से बचा जाए। लेकिन ट्रम्प नहीं माने और बदली हुई परिस्थितियों में बाकी सभी एकजुट हो आपदा में अवसर तलाशने लगे तो कहीं अमेरिका ही हासिए पर न चला जाए? अच्छा होता कि इतना तो ट्रम्प समझ पाते!

महावीर की प्रासंगिकता

कैलाश मड़बैया

महावीर स्वयं में ही बाह्य शत्रुओं को जीतकर नहीं, अंत: के दुश्मनों को जीतकर आत्मसाधना से महान बनने का नाम है। महावीर स्वामी ने लगभग 2600 वर्ष पूर्व स्व में उतरने के जो वैज्ञानिक प्रयोग सिद्ध किये थे उन्हें विज्ञान भले आज सिद्ध कर पाया हो। पर वह क्रांतिकारी महावीर ही थे जिन्होंने मानव/पशु बलि के पाखण्ड वाले उस पतित युग में कहा था कि मुक्ति/मोक्ष के लिये किसी पर यानी शास्त्र, गुरू और ईश्वर तक की आवश्यकता नहीं वरन स्वयं को पर्त दर पर्त उघाड़ कर आत्मस्थ होने की आवश्यकता है। पर तब तो इसको गहराई से समझे बिना जैन धर्म को ही नास्तिक होने का आरोप लगा दिया गया था। वह तो अब महावीर को समझा गया जब आइन्सटीन जैसे वैज्ञानिक का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। इसलिये आइये तेइस तीर्थकरों की समर्थ जिन पर परम्परा से हटकर महावीर ने जो कतिपय अभिनव सिद्धांत दिये थे उन्हें संक्षेप में व्याख्यायित करने की विनम्र कोशिश करें।

अनेकान्त दर्शन- महावीर के काल अर्थात ईसा से 599ई. पूर्व तक अरस्तू का ही सिद्धांत प्रचलित था कि क, क है और ख, ख है। क, ख नहीं हो सकता और ख, क नहीं। पर महावीर ने समझाया कि एक व्यक्ति पुत्र के लिये पिता, पत्नी के लिये पति, पिता के लिये पुत्र, बहिन के लिये भाई अर्थात अलग -अलग रूप हो सकते हैं इसलिए वस्तु का स्वरूप सापेक्ष होता है ठीक पांच अंधों के अलग-अलग हाथी देखने के अनुभवों की तरह। पर भिन्न-भिन्न अनुभव होने के बावजूद हाथी तो सभी का देखा हुआ समग्र अनुभव ही होता है न कि किसी एक का। एक व्यक्ति की दृष्टि तो एक कोने तक ही जा सकती है, एक साथ सभी कोणों तक नहीं इसलिए एक व्यक्ति की दृष्टि एकांगी होगी, सम्पूर्ण सत्य तो सभी कोणों को मिलाकर ही बनेगी। इसलिए आप जो कह रहे हैं वह ही सही नहीं है वरन दूसरा जो कहता है वह भी सत्य है। सत्य एकांगी नहीं, विराट होता है, समग्र होता है। संक्षेप में यही महावीर की अनेकान्त दृष्टि है।

श्रावक-तीर्थकर सामान्य अर्थ भव सागर तारने से यानी जन्म-मृत्यु के बंधनों से मुक्ति दिलाने से है। इसके लिये इनके अनुयायियों को एक शब्द दिया गया है श्रावक। यह साधारण शब्द नहीं है यों इसका सामान्य बोध सुनने से है पर श्रोता और श्रावक में बहुत फर्क है। श्रोता एक कान से सुनता है और संभव है दूसरे से निकाल भी दे पर श्रावक का अर्थ सम्यक सुनने से है जो प्राणों से सुनता है। यह क्रिया दो तरह से होती है एक तो प्रतिक्रमण जो आक्रमण के विपरीत होती है। जहां-जहां मन के ध्यान पर आक्रामण हुआ है अर्थात भटका हुआ है पहले प्रतिक्रमण से वहां से समेटना, केंद्रीभूत करना और चित्त का निर्विचार होना। दूसरे चरण में प्रक्रिमण से लौटे चित्त को तुरंत आत्मस्थ करना। चित्त खाली नहीं रह सकता। तुरंत काम दो, प्रथमत: यह निर्विचार होना साधना से ही संभव है यद्यपि है यह बड़ा ही स्वाभाविक पर भटकते कर्म बंधों में लिप्त होने से कठिन है, सहज नहीं जब वक्ता और श्रोता की एक 'फ्रिक्वेंसी,' आवृत्ति की एक मानसिकता हो जाती है तभी दिव्य ध्वनि सुनी जा सकती है। भाषा इसमें बाधक नहीं होती। ऐसे समझ लीजिये कि इन दिनों जैसे संसद में ऐसा गण-उपकरण सांसदों के कानों में लगाया जाता है कि किसी भी भाषा में संसद में दिया गया वक्तव्य प्रत्येक सांसद अपनी भाषा में समझ लेता है क्योंकि वह कानों में लगा उपकरण अनुवाद कर उनकी ही भाषा में श्रवण संप्रेषण करा देता है इसलिए समवशरण में तीर्थकर की दिव्यध्वनि प्रत्येक प्राणी यदि अपनी भाषा में उन दिनों समझ सकता था तो विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं रह जाता पर प्रतिक्रमण से लौटे ध्यान को तत्काल आत्मरत कराना अनिवार्य है।

सामायिक- श्रावक केवल सुनता नहीं है वरन सम्यक श्रवण कर उसी समय आत्मस्थ करता है। यही सामायिक उपर्युक्त वर्णन से यह शब्द आगे जाता है समय का दूसरा अर्थ होता है आत्मा। यहां महावीर की वैज्ञानिकता को आइस्टीन ने 2500 वर्ष बाद यों पुष्ट किया। चूंकि किसी अस्तित्व को क्षेत्र और समय से जाना जाता है। जो प्राय: प्रथक प्रथक माने जाते रहे। आइंसटीन के सापेक्षबाद के उपरान्त कहा गया है कि काल और क्षेत्र अलग नहीं वरन एक ही हैं। भौतिक पदार्थ को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में दर्शाते है पर इनमें एक के भी बिना अस्तित्व संभव नहीं तब प्रश्न उठा कि कब? उसका अस्तिव वैसा है? आइंस्टीन ने कब अर्थात समय यहां अनिवार्य माना है इसे आध्यात्मिक दृष्टि से महावीर ने भी समय को चेतना का अनिवार्य अंग माना। समय ही चेतना की दशा तय करता है। समय ही शास्वत है आदि अनादि है। यही आत्मा है।

जाति स्मरण- यह एक तिलस्माई सा शब्द है जिसका संबंध वस्तुत: साधना से तो है पर विज्ञान अभी तक इस दिशा में बहुत कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए जीवन रहस्यमय बना हुआ है। किस्से कहानियों में तो बहुत कुछ मनगढ़ंत चलता है पर अध्यात्म में जीवन सहज माना जाता है क्योंकि जो ध्यान में उतरते हैं वे प्रकृति के इस गहरे राज को समझ लेते हैं। यों तो प्रकृति ने सभी अनुकूल व्यवस्थायें कर दीं है कि मनुष्य को जितना आवश्यक है उतना ही स्मरण रखे। पूर्व जन्म की बातों की न उसे जरूरत है और उसे याद रखना चाहिये। इसलिए अनावश्यक भूलना ही उचित है आदमी को अन्यथा इतना गड्डमगड्ड हो जायेगा कि स्मृतियों के भारीपन से मनुष्य की नसें फट जायेंगी, लेकिन आवश्यक हो तो साधक कोशिश करे ध्यान में उतरने की। फिर यह संभव है कि मनुष्य पूर्वभव देख सकता है और यदि प्यास गहरी है तो अतीत के कई भावों में भी उतर सकता है।

वीतराग-उपर्युक्त अनुसार राग से छूटकर त्याग से बंधकर विरागी नहीं वरन आत्मस्थ होकर निर्विकारी होना ही वीतरागी होना है। सहज स्वभावी होना है। द्वंदों से परे उठना है पर से भिन्न होकर स्व में रत होना है यह कहीं न कहीं से बंधने की मूर्छा तोड़ना है। यह जागृति या 'अवेयरनेस' होना जरूरी है। जातिस्मरण और वीतराग अन्योन्याश्रित है परस्पर अंत:संबंधी है महावीर से पूर्व प्राय: यह शब्द नहीं था भाव तो था तभी तो मुक्ति संभव हुई थीं। पर बिना जाति स्मरण के कामना से परे उठना संभव नहीं लगता, राग के परे/ वियोंण्ड होना कठिन है सीभ धर्म राग छोड़ने की तो कहते है विरागी भी, पर वीतरागी महावीर के अतिरिक्त कोई नहीं बनाता। इसीलिये महावीर के वीतराग का कोई जोड़ नहीं वह सचमुच लाजवाब है।

महावीर को 23 तीर्थकरों की समर्थ और विकसित परम्परा तो मिली थी पर इस तरह की वैज्ञानिकता नहीं थी अत: महावीर ने कुछ अनूठे प्रयाग किये थे जिनकी पुष्टि भले बाद में ही सही, हुई और वे खरे भी उतरे। अहिंसा अपरिग्रह, अचौर्य, सत्य और ब्रम्हचर्य तो महावीर से पहले भी थे और यह जिन के लिये अनिवार्य भी हैं, पर श्रावक, वीतराग, अनेकान्त, सप्तभंगी, स्यादवाद, सामायिक आदि कतिपय प्रयोग महावीर के अनूठे और अति वैज्ञानिक थे। जो आज भी सचमुच प्रासंगिक ही नहीं मनुष्य जीवन में अपनाना आवश्यक हैं। यही इस युग की हर समस्या के निदान हैं। गौतम बुद्ध और बाद में महात्मा गांधी के प्रयोग इनके ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने हैं।

आजकल

कांग्रेस में आंतरिक कलह

कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच विवाद जारी है, जिससे पार्टी के लिए समस्याएं बढ़ रही हैं। इसी तरह की गुटबाजी कांग्रेस के अन्य राज्यों में भी देखी जा रही है, जिससे केंद्रीय नेतृत्व की कमजोरी सामने आ रही है। कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बीच का विवाद अभी भी जारी है, जो पार्टी के लिए सही नहीं है। इन दोनों नेताओं के बीच कलह की बात वक्त-वक्त पर सामने आती रही है और शीर्ष नेतृत्व अभी तक इसे सुलझाने में नाकाम रहा है।

सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार का टकराव वर्चस्व की लड़ाई है। दोनों नेता राज्य संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ राजस्थान में भी देखने को मिला था, जहां आखिरकार पार्टी को सत्ता गंवानी पड़ी। बिल्कुल वही सब अब कर्नाटक में हो रहा है। यह बिल्कुल अप्रत्याशित स्थिति है, जहां सीएम और उनके मंत्री चाहते हैं कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा दे दें। जब इस तरह साफ-साफ दो गुट बन गए जाएं, तो न संगठन ठीक से चल सकता है और न सरकार।

कांग्रेस की इस समय केवल तीन राज्यों में सरकार है - कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। झारखंड और जम्मू-कश्मीर में वह सरकार का हिस्सा जरूर है, लेकिन जूनियर पार्टनर के रूप में। जहां पार्टी की अपनी सरकार है, वहां भी सब ठीक नहीं लग रहा। कर्नाटक की कहानी तो चल ही रही है, तेलंगाना और हिमाचल से भी गुटबाजी की खबरें आती रही हैं। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नौ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी और पार्टी के उम्मीदवार को हार मिली थी।

लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने 99 सीटें जीतीं, तो लगा कि पार्टी वापसी की राह पर है। लेकिन, एक के बाद एक विधानसभा चुनावों में हार ने उसे फिर बेपटरी कर दिया। उसने लोकसभा चुनाव से जो भी बढ़त कमाई थी, वह हरियाणा और महाराष्ट्र में मिली हार में खर्च हो गई। और इसके पीछे वजह रही गुटबाजी। दोनों राज्यों में स्पष्ट तौर पर पूरा संगठन बंटा नजर आ रहा था, पर केंद्रीय नेतृत्व सही वक्त पर कठोर फैसले लेने में नाकाम रहा। कांग्रेस के अंदर कलह का असर विपक्ष के बाकी दलों के साथ उसके रिश्तों और आई.एन.डी.आई.ए. ब्लॉक में उसकी स्थिति पर भी पड़ रहा है। यूपी उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा इलेक्शन, कहीं भी साथी दलों ने कांग्रेस को भाव नहीं दिया।

अपने गिरेबां में झांकें मुस्लिम रहनुमा

फरमान अली

केंद्र की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली राजग सरकार ने संशोधित वक्फ बोर्ड बिल पास कर दिया और राष्ट्रपति ने उसको मंजूरी भी दे दी। अब वक्फ कानून आठ अप्रैल से देशभर में लागू हो गया है। इस बिल के क्या फायदे होंगे क्या नुकसान होगा यह बात इतर है ,लेकिन इस ऐतिहासिक कदम के बाद उन मुस्लिम रहनुमाओं को अपने गिरेबां में झांकना होगा कि आखिर केंद्र सरकार को यह कदम क्यों उठाना पड़ा? वक्फ बोर्ड की भूमि की बंदरबाट, भ्रष्टाचार और कुछेक परिवारों का कब्जा इसकी प्रमुख है। आज वक्फ बोर्ड की हजारों एकड़ जमीन अदालती झमेलों में फंसी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस विकट स्थिति के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है। अब यह सवाल तो उठेगा ही और रहनुमाओं को जवाब देना चाहिए।

संशोधित बिल पास होने के बाद जहां सुप्रीम कोर्ट में धड़ाधड़ याचिकाएं डाली जा रही हैं, वही एक हारे हुए जुआरी की तरह मुस्लिम रहनुमा भी केवल और केवल खोखली बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही कथित तौर पर उनके रहनुमा कहे जाने वाले राजनीतिक दलों के नेता क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। यह सवाल भी देश पूछ रहा है।

इस बिल का क्या असर होगा? क्या आम मुसलमान को इसका लाभ मिल पाएगा ? अभी हम इस बहस पर नहीं जाना चाहते लेकिन हमारा मानना है कि मुसलमान वक्फ प्रॉपर्टी के केयरटेकरों को इस पर गंभीरता से सोचना होगा। पिछले सैकड़ों सालों के दौरान वक्फ संपत्ति के साथ ये लोग कितना इंसाफ कर पाए हैं? यह किसी से छुपा नहीं है। उनके बुजुर्गों ने समाज लिए जो जमीन और अपनी कीमती संपत्ति वक्फ की थी, उनका क्या

मकसद था ? क्या इन केयरटेकरों ने उनके मकसद के हिसाब से आम लोगों को या आम मुसलमान को उनका हक देने की कभी कोशिश की या फिर माफिया या बड़े पैसे वालों को वक्फ की संपत्ति चंद पैसों में लेकर सौंप देने का काम किया? अब सरकार ने एक कदम उठाया तो ये लोग क्यों लोग बिलबिला रहे हैं। क्या इन लोगों को पहले नहीं सोचना चाहिए था कि आखिर वक्फ की संपत्ति की बंदरबांट क्यों हो रही है? मुसलमान की शिक्षा और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए आखिर इन लोगों ने काम क्यों नहीं किया किया। वक्फ संपत्ति का बंदरबाट करना या फिर अपने परिवार के लोगों का लालन-पोषण करना ही इनका मकसद रह गया था? यह बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आज समुदाय की जनता को इन लोगों को देना होगा। आखिर क्यों इस्लामी सिद्धांतों के मुताबिक यह लोग यह इंसाफ नहीं कर पाए। यह बेहद गंभीर मामला है। आगे इस तरह के मसले ना हों तो मुस्लिम रहनुमाओं को अब इस पर पहल करनी होगी। गंभीरता दिखानी होगी और गंभीर मंथन करना होगा। हूबहू इस्लाम में जो मकसद इस तरह के मामलों में दिया गया ,उसके अनुरूप काम करना होगा। यदि यह लोग ऐसा करते तो शायद वक्फ संशोधन बिल की आवश्यकता नहीं पड़ती।

हम यह नहीं कहते कि इसको लेकर सरकार की मंशा अच्छी है या बुरी। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो गड़बड़, भ्रष्टाचार और घोटाले थे और इस गड़बड़ी के विरोध में आज तक कोई भी रहनुमा क्यों नहीं आगेआया। सबसे बड़ा सवाल यही है। आम मुसलमानों को भी इस पर पैनी नजर रखनी होगी। उन्हें रहनुमाओं से सवाल करने होंगे। न कि इस्लाम के नाम पर उनके समर्थन में हां में हां मिलानी होगी। आम लोगों को इस पर सवाल करना चाहिए कि आखिर इसकी नौबत क्यों आई ? आगे उनकी क्या मंशा है?